साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 25-31 दिसंबर 2023 वर्ष-9, अंक-37
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

देशभर के 60 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया नया अध्याय

» ट्रैक्टर की बजाए हल से खेती करने के फायदे

» रासायनिक खाद नहीं जैविक का उपयोग करेंगे

अब प्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ेंगे कृषि स्नातक विद्यार्थी

भोपाल। जागत गांव हमार

जलवायु परिवर्तन से हो रहे फसलों को नुकसान और खेती में बढ़ते रसायनिक खाद के उपयोग के दुष्परिणाम ने देश के कृषि शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इससे निपटने के लिए उन्होंने कृषि पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। यह बदलाव 2023-24 के नए शिक्षा सत्र से दिखाई देंगे। अब कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को माडल खेती के साथ प्राकृतिक खेती का पाठ भी पढ़ाया जाएगा।

नए स्लेबस में प्राकृतिक खेती - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि जबलपुर समेत देश के 60 से ज्यादा कृषि विवि के बैचलर आफ एग्रीकल्चर साइंस यानी बीएससी एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती के विषय को जोड़ा है। अब विद्यार्थी को प्राकृतिक खेती के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन दिनों जनेकृविवि ने 11 दिसंबर से स्नातक का नया सत्र शुरू कर दिया है, जिसमें नए स्लेबस में प्राकृतिक खेती से जुड़े सभी विषयों को जोड़ा गया है।

मालगुजारों से संपर्क किया

कृषि शिक्षा का सिलेब्स बनाने वाले विशेषज्ञों ने गांव के किसानों और परंपरागत खेती करने वाले मालगुजारों से संपर्क किया। उनके खेती करने के गुर का अध्ययन किया। इससे होने वाले फायदों का डाटा तैयार किया। परंपरागत खेती से हो रहे फायदे और इस ओर से किसानों के दूरी के कारणों का पता लगाया। इसे माडल खेती से जोड़ने और इससे होने वाले फायदों के अध्ययन के बाद पूरा कोर्स तैयार किया गया है। इसमें हर वह जानकारी है, जो सालों से गांव में हो रही खेती के तरीकों में अपनाई जाती है।

जनेकृविवि समेत देशभर के कृषि विवि में संचालित हो रहे बैचलर आफ एग्रीकल्चर साइंस कोर्स में इस बार से प्राकृतिक खेती के विषय को जोड़ा गया है। इस सत्र से विद्यार्थी इसकी पढ़ाई करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि विद्यार्थियों को क्लास में माडल खेती और प्राकृतिक खेती में फर्क समझ आएगा। वे भी इससे जुड़ेंगे।
-डॉ. धीरेंद्र खरे, डीन फैकल्टी,
जनेकृविवि, जबलपुर

सीएम बोले | पीएम ने प्राकृतिक खेती को किया प्रोत्साहित

प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी के विकास के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। जनता के हित में लगातार कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिला पांढुर्णा में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो छोटे, नवीन और पिछड़े जिले हैं, उनकी क्षेत्रानुसार स्थानीय कठिनाइयां है। इन कठिनाइयों को मौके पर जाकर समझना और समाधान करना जरूरी है। जिला बनने के बाद जिले

की स्थानीय परेशानियों को दूर कर उसका विकास करना राज्य शासन का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने पांढुर्णा के पाथई और कोडिया ग्राम के निवासियों से संवाद किया। ग्राम पाथई के किसान राहुल कुमार से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करते हुए सभी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया है। प्राकृतिक खेती से खेती की लागत में कमी आती है और उसके अनुपात में फसल की कीमत अधिक मिलती है। जमीन की उर्वरता बनी रहती है। कृषक राहुल ने बताया कि उनकी 10 एकड़ जमीन है। जिसमें वो पूरी तरह प्राकृतिक खेती करते हैं। शासन की योजना का लाभ लेकर नवरतन नाम का आटे का यूनिट भी लगाया है। एक अन्य कृषक ने भी मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान कल्याण योजना से साल में 12 हजार रुपए मिलते हैं।

ग्राफ्टिंगः टमाटर-बैगन के पौधे अलग से किए जाते है तैयार

भोपाल के किसान एक ही पौधे में उग रहे बैगन और टमाटर

भोपाल। जागत गांव हमार

सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए बैगन के साथ टमाटर मिलाने का काम रसोई में होता रहा है, लेकिन भोपाल के किसान ने एक ही पौधे में बैगन और टमाटर के फल उगाने शुरू किए हैं। उन्होंने ग्राफ्टिंग की तकनीक अपनाकर ऐसा किया है। खास बात यह भी है कि जिस पौधे में ये दोनों सब्जियों की फसल एक साथ ली जा रही है, उसकी जड़ जंगली पौधे की है। जड़ जनित रोगों से निजात पाने के लिए किसान मिश्रीलाल ने कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में लंबे समय तक प्रयोग करने के बाद इस तकनीक में सफलता प्राप्त की है। काले रंग का गेहूं, नीला आलू और लाल रंग की भिंडी उगाकर सुर्खियों में रहने वाले भोपाल के खजूरीकलां के किसान मिश्रीलाल राजपूत फिर चर्चा में हैं। इस बार इन्होंने अपने खेत में एक ही पौधे से टमाटर और बैगन की फसल लेना शुरू किया है।

शिमला मिर्च की खेती

मौसम के अनुसार बैगन तो बिक्री के लिए बाजार भी जाने लगे हैं। टमाटर में फूल लगाने के साथ छोटे-छोटे फल लगने लगे हैं। सफल प्रयोग से उत्साहित होकर उन्होंने खेत में शिमला मिर्च के साथ अन्य किस्मों की फसल भी एक ही पौधे से लेने की तैयारी शुरू कर दी है। मिश्रीलाल ने बताया कि इस प्रयोग के लिए बैगन की जंगली प्रजाति के पौधे का चयन किया जाता है। टमाटर एवं बैगन के पौधे अलग से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद जंगली पौधे के तने से टमाटर एवं बैगन के पौधे को ग्राफ्टिंग करके संबद्ध कर दिया जाता है।

रोग मुक्त पौधे

सफल ग्राफ्टिंग होने पर टमाटर, बैगन के मूल पौधे की जड़ों को अलग कर दिया जाता है। इसके साथ ही जंगली प्रजाति के पौधे की जड़ से टमाटर एवं बैगन के पौधों का पोषण होने लगता है। उन्होंने बताया कि वह बैगन और टमाटर की फसल में लगने वाले उकसा रोग से काफी परेशान थे। वर्तमान में भी उनके खेत में सामान्य बैगन की फसल में उकसा रोग लग गया है, लेकिन ग्राफ्टिंग तकनीक से लगे पौधे सुरक्षित हैं।

किसान ने ग्राफ्टिंग की रूट स्टोक तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस पद्धति से फसल को मृदा जनित बीमारियों से मुक्ति मिलती है। उत्पादन भी बढ़ता है। इस तकनीक से एक ही पौधे में तीन से चार किस्म की सब्जियों की फसल भी ली जा सकती है।
- डॉ. भोपाल सिंह, अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली पूसा

बैंक में जमा निधि के ब्याज से होगी बढ़ी राशि की भरपाई

तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में एक हजार का इजाफा

» पूरे मध्य प्रदेश में 43 लाख के करीब तेंदूपत्ता संग्राहक

भोपाल। जागत गांव हमार

नवगठित मोहन सरकार ने भाजपा के संकल्प के अनुसार तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में एक हजार रुपए की वृद्धि तो कर दी है, लेकिन इसकी भरपाई राज्य लघु वनोपज संघ के बैंक में जमा निधि पर मिलने वाले ब्याज से ही की जाएगी। पहले तेंदूपत्ता संग्राहकों को तीन हजार रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक मिलता था जो अब बढ़ाकर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। हालांकि, इस बढ़ोत्तरी में वन विभाग ने यह भी प्रविधान किया है कि पारिश्रमिक दर के भुगतान में अतिरिक्त राशि की जरूरत होती है तो लघु वनोपज संघ अपनी बैंक में जमा निधि पर मिलने वाले ब्याज से इसकी भरपाई करेगी। इसके बाद भी बढ़ी दर की भरपाई नहीं हुई तो संघ तेंदूपत्ता संग्राहकों को हर साल मिलने वाले लाभांश की राशि से इसकी भरपाई करेगा, इससे लाभांश की राशि कम हो जाएगी।

प्रदेश में 43 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक

मध्य प्रदेश में 25 लाख तेंदूपत्ता परिवार है और 43 लाख के करीब तेंदूपत्ता संग्राहक है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही विधानसभा चुनाव के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को साधने के लिए तीन हजार रुपये की जगह चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा देने का वादा किया था। अब सत्ता में भाजपा की मोहन सरकार है। सरकार बनते ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को चार हजार रुपये मानक बोरा देने का आदेश हो गया है, लेकिन इसके लिए अलग से बजट नहीं दिया जाएगा। इसकी भरपाई राज्य लघु वनोपज संघ के बैंक में जमा निधि पर मिलने वाले ब्याज से ही की जाएगी।

मध्यप्रदेश संकल्प पत्र की गारंटी से खेती बनेगी लाभ का धंधा

» सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने बनेगी सीएम सिंचाई टास्क फोर्स

» सीएम डॉ. मोहन यादव ने सात दिन में कार्य शुरू करने के दिए निर्देश

उज्जैन में चना और डिंडोरी में खुलेगा श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान

भोपाल। जागत हमार हमार

खेती की समृद्धि के लिए 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सिंचाई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। मप्र संकल्प पत्र-2023 में सिंचाई सुविधाओं विस्तार करते हुए खेती को आधुनिक और समृद्ध बनाने की गारंटी दोहराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संकल्प-पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी है। इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सभी विभागों को सात दिन में रोड-मेप बनाकर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए है। ग्वालियर एवं चंबल में माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना, नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद में चिंकी-बोरास बैराज परियोजना, नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा में शक्कर-पेंच लिंक संयुक्त परियोजना, छिंदवाड़ा में पेंच डायवर्सन परियोजना, खंडवा में खंडवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना पन्ना में रूंझ मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना पन्ना, रीवा, सतना, कटनी एवं जबलपुर में बरगी परियोजना, कटनी में बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, हरदा में शहीद इलाप सिंह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, श्योपुर में चेंटीखेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना, सतना एवं रीवा में बहुती नहर परियोजना पूरी होने से प्रदेश का कृषि परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा।

उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान और डिंडोरी में श्रीअन्न अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। सोयाबीन फसल को सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से श्री अन्न उत्पादकों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति फसल सम्मान राशि दी जाएगी। श्री अन्न की फसल बोने पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम में सब्सिडी दी

शुरू होगा मिशन दाल

अगले 5 वर्षों में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश में मिशन दाल शुरू किया जाएगा। सरकार द्वारा एमएसपी पर अरहर, मूंग, उड़द एवं मसूर जैसी सभी दालों की खरीद की व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। दाल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे । इससे दाल की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू चेन को बढ़ावा मिलेगा। बागवानी का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर बढ़ावा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश फ्लोरीकल्चर मिशन बनाकर मध्यप्रदेश को फलोरीकल्चर में नम्बर वन बनाया जाएगा।

12 हजार किसान सम्मान निधि

पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 80 लाख से अधिक किसानों को हर साल 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिल रही है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं में 3 लाख करोड़ से अधिक के लाभ दिए गए है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को पिछले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। इसके आलावा 44,600 करोड़ से ज्यादा लागत की केन-बेतवा सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिल गई है।

बिजली में 93 फीसद सब्सिडी

पांच हॉर्स पावर तक के पंप उपयोग करने वाले 32 लाख किसानों को बिजली बिल पर 93 फीसद सब्सिडी मिल रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। पशुपालकों को पशु उपचार की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराते हुए 400 से अधिक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित है।

पीएम किसान समृद्धि केंद्र

किसानों को ब्याज रहित लगभग 4 लाख करोड़ का फसली ऋण दिया गया है। यह आगे भी किसानों को मिलता रहेगा। बीज, फर्टिलाइज़र, मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 5,000 नए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करके किसानों को सस्ते दाम में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

65 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई

कृषि के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता 7.6 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2023 तक 47 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया जाएगा। हम 4 लाख हेक्टेयर तक की उपजाऊ भूमि में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के डार्क जोन क्षेत्रों में बोरवेल, पुनरुद्धार के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और इस क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश होगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के कनेक्शन दिए जाएंगे।

सरसों उत्पादक प्रदेशों में मप्र होगा

सरसों उत्पादन प्रोत्साहित करते हुए देश के अग्रणी सरसों उत्पादक प्रदेशों में मध्यप्रदेश को शामिल किया जाएगा। इसके लिये सरसों उत्पादक जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में सरसों खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों-के लिए किसान उत्पादक संगठन स्थापित किया जाएगा और उन्हें सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

भोपाल में एक्वा पार्क का निर्माण होगा

पशु एवं पोल्ट्री चारा निर्माण यूनिट स्थापित की जाएगी जिससे किसानों को उचित मूल्य पर चारा मिल सके। इसके लिए मध्यप्रदेश पोल्ट्री विकास मिशन शुरू किया जाएगा। भोपाल में एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा। बालाघाट, मंडला, शहडोल, छतरपुर एवं इंदौर में मछली बीज हैचरी यूनिट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेशम उत्पादन एवं मधुमक्खी को बढ़वा देने के लिए मदद दी जाएगी। किसानों को मधुमक्खी पालन एवं शहद मधुमक्खियों के डिब्बे एवं टूलकिट दिए जाएंगे।

हर जिले में बनेगा गौवंश विहार

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। पशुओं की बीमारी के इलाज एवं पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत सभी दुधारू एवं अन्य पशुओं के लिए मुफ्त बीमा एवं उनके रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। बीमार एवं सड़क हादसों में घायल पशुओं के उपचार के लिए पशु एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक जिले में एक गौवंश विहार स्थापित किया जाएगा।

जागत गांव हमार

उम्मीदों को पंख

» मिलेट्स क्वीन ने कहा-श्री अन्न को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेरे जैसी चाहिए कई लहरी बाई

श्रीअन्न को बचाएं, सेवन करें और आगे बढ़ाएं, इसी में हमारी भलाई

भोपाल। जागत गांव हमार यूनेस्को ने 2023 के साल को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मध्यप्रदेश के डिंडोरी की लहरी बाई ने इस मिलेट्स का बीज बैंक तैयार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लहरी बाई की तारीफ की और उन्हें मिलेट्स एम्बेसडर घोषित किया है। डिंडोरी की दुनिया में पहचान बन चुकी लहरी बाई का कहना है कि श्रीअन्न को संरक्षित करें, इनका सेवन करें और आगे बढ़ाएं। इसी में हमारी भलाई है। जिस प्रकार अपने शरीर का शृंगार हम खुद से करते हैं उसी प्रकार धरती का शृंगार श्रीअन्न से करें, तभी हमारी धरती सुंदर होगी और हम स्वास्थ्य होंगे। दरअसल, वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स डे पर आयोजित वाइस आफ मिलेट्स कार्यक्रम शामिल होने भोपाल आई थीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने काम पर गर्व है। मैं अपना काम वैसे ही करती रहूंगी, लेकिन बड़ी कंपनियों के माध्यम से नहीं। हमारा स्वसहायता समूह ही इस काम को आगे बढ़ाएगा।

दादी से सीखा बीच संजोना

यूनेस्को ने 2023 के साल को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, लेकिन लहरी बाई ने मिलेट्स को बचाने का संघर्ष उस समय शुरू कर दिया था, जब इस श्री अन्न की ताकत दुनिया के सामने आई भी नहीं थी। दादी से किस्से कहानियां सुनते हैं बच्चे...बैगा जाति की लहरी बाई ने अपनी दादी से जीवन के बीज संजोना सीखा।

पारंपरिक खेती में दिक्कत हुई

लहरी बाई का कहना है कि बीज बैंक का काम मैंने यह सोच कर आरंभ नहीं किया था कि मुझे शोहरत मिलेगी। मैं खेतिहर बैगा समुदाय से हूं। जब मैं करीब 12 साल की थी तब हमें पारंपरिक खेती में दिक्कत हुई, क्योंकि बीज नहीं मिल रहे थे। मेरे दादा और दादी ने इस समस्या पर विचार किया और मुझसे बोले कि यदि यही हालात रहे तो एक दिन मोटे अनाज की किस्में विलुप्त हो जाएंगी। उनके कहने पर मैंने बीज संरक्षण आरंभ किया और बीज बैंक बनाया।

मोटा अनाज उगाना जरुरी

जिसे पीएम मोदी ने श्री अन्न नाम दिया है। उस मोटे अनाज यानि मिलेट्स के बीज जब खत्म होने लगे तो लहरी बाई ने अपने घर के दो कमरों में बीज बैंक तैयार कर लिया। इस बीज बैंक में तैयार हुए बीज लहरी बाई आस पास के जिलों तक पहुंचाती हैं। किसानों को बताती हैं कि मोटा अनाज उगाना क्यों जरुरी है।

दादी ने पकड़ी थी मेरी कमजोरी

एक खास चर्चा के दौरान लहरी बाई ने कहा कि अकेली लड़की हूं, ज्यादा रेंग नहीं सकूं। दुनिया भर में ये ताकतवर दाना पहुंचाना हो तो और नई लहरी बाई जरुरी है। बचपन में लहरी बाई अक्सर बीमार रहती थीं। उनकी दादी ने जान लिया था कि ज्यादा चावल खाने और कोदू, कुटकी जैसे मोटे अनाज से दूर रहने की वजह से उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर है। दादी का नुसखा लहरी पर आजमा कर खत्म भी हो सकता था, लेकिन लहरी ने दादी के बीज मंत्र को बीज बैंक के जरिए बचा लिया।

हमने बीज बैंक बनाया

लहरी बाई ने धीरे-धीरे खेती में खत्म हो रहे इस श्री अन्न को सहेजना शुरू किया। बीज तैयार किए। किसानों को वो बीज दिए, फिर बीज तैयार किए। लहरी बाई का कहना है कि ये अनाज धीरे-धीरे खत्म हो रहे थे, तो हमने बीज बैंक बनाया। अब मैं आस पास के जिलों में जाकर ये बीज किसानों को देकर आती हूं। खास बात यह है कि इसके बदले में भी लहरी बाई केवल अनाज ही लेती हैं। एक बीज से बीज बैंक तक की पूरी कवायद लहरी बाई की अपनी मेहनत थी।

जानी श्रीअन्न की ताकत

लहरी बाई का कहना है कि मैं दस बारह साल की थी, चावल ज्यादा खाती थी और बहुत बीमार पड़ती थी। तब दादी कोदू कोटकू लाईं। फिर जब ये खत्म हो जाता तो मैं कहती थी कि अब और ले आना। धीरे-धीरे जब ये खत्म ही होने लगा तो दादी ने कहा कि ये ताकतवर दाना है। बेटी इसे खोज। उससे पेट दर्द ठीक हो जाता है। बीमार नहीं पड़ते तो मैंने फिर बीज इकट्ठे करने शुरू किए और डेढ़ सौ बीज जमा कर लिए। धीरे-धीरे घर के ही कमरे में बीज बैंक तैयार कर लिया।

- हरित क्रांति के बाद कुछ विसंगतियां भी आईं। गेहूं-चावल के कारण पारंपरिक अनाज के बने व्यंजन थाली से गायब हो गए। हमें बीमारियों ने घेर लिया है। हमें श्रीअन्न की ओर लौटना होगा, जो वास्तव में स्वदेशी है।

मनोज श्रीवास्तव, पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन

- लहरी बाई पूरी दुनिया में डिंडोरी जिले की पहचान हैं। डिंडोरी में श्रीअन्न की कम्पलीट चैन है। पौधे के संरक्षण से लेकर प्रोडक्शन तक और स्व-सहायता समूह के जरिए बिक्री तक सब कुछ डिंडोरी में होता है।

नेहा धूरिया, साहायक संचालक, कृषि विभाग,डिंडोरी

भारत में 44 फीसदी ऑपरेशन गैरजरूरी होते हैं...

भारतीय डॉक्टरों की पेशेवर दक्षता पर मुझे इतना विश्वास है कि बांग्लादेश में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मेरे दोस्तों-रिश्तेदारों को भारत आकर इलाज कराने के लिए कहती हूं। मेरे जो परिचित दूसरे देशों में हैं, उनसे भी कहती हूं कि शरीर की जांच या बीमारी के इलाज की अगर जरूरत पड़े, तो अस्पतालों में भारतीय चिकित्सकों को तरजीह दें। मैं भी जब अमेरिका जाती हूं, और चिकित्सीय जांच की जरूरत पड़ती है, तब अस्पतालों में पता करती हूं कि भारतीय डॉक्टर हैं या नहीं। अगर भारतीय डॉक्टर होते हैं, तो श्वेत अमेरिकियों को दरकिनार कर भारतीय डॉक्टर से सलाह लेती हूं।

भारत से बाहर भारतीय चिकित्सकों पर मुझे इतना भरोसा क्यों है? इसका कारण क्या यह है कि हमारा इतिहास एक है? इसकी वजह क्या यह है कि एक ही उपमहाद्वीप का हिस्सा होने के कारण हम निकटता महसूस करते हैं? ये सब कारण तो हैं ही, लेकिन असल कारण यह है कि पेशेवर दक्षता की कसौटी पर भारतीय डॉक्टर दूसरे देशों के डॉक्टरों से बहुत आगे हैं। भारतीय युवा मुश्किल प्रतियोगिताओं में बैठकर और पास होकर मेडिकल में दाखिला लेते हैं, फिर कठिन परीक्षा पास कर डॉक्टर बनते हैं। भारत से बाहर विकसित देशों तक में भारतीय डॉक्टर इतने सफल हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पेशेवर दक्षता ही है। यह अलग बात है कि पिछले साल के एक भीषण व्यक्तिगत अनुभव के बाद मेरी यह धारणा कुछ हद तक खंडित हुई है कि सभी भारतीय चिकित्सक अच्छे और अपने पेशे के प्रति ईमानदार ही होते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की खबरें बीच-बीच में आती रहती हैं। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल के एक विख्यात हृदयरोग विशेषज्ञ को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने कुल छह सौ मरीजों के शरीर में नकली और खराब पेसमेकर लगाए थे। पता यह चला कि जिन लोगों को पेसमेकर की जरूरत नहीं थी, उनके शरीर में भी जबरन पेसमेकर लगाए गए थे। इनमें से अनेक लोगों की या तो मृत्यु हो गई, या फिर वे शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया भला? क्योंकि उन्हें टारगेट पूरा करना था। जाहिर है, ऐसा उन्होंने पैसा कमाने के लिए ही किया। एक आंकड़ा बताता है कि भारत में 44 फीसदी ऑपरेशन गैरजरूरी होते हैं। यानी जहां सर्जरी की जरूरत नहीं है, वहां भी सर्जरी की जाती है। भारत में दिल के 55 फीसदी, गर्भाशय के 48 प्रतिशत, कैंसर के 47 प्रतिशत, घुटना प्रत्यारोपण के 48 फीसदी और 47 प्रतिशत सिजेरियन ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। अस्पतालों

लेखक-तस्लीमा नसरीन

का कॉरपोरेटीकरण हो चुका है, इसी कारण बड़ी संख्या में सर्जरी की जरूरत है। ज्यादातर अस्पताल अब लोगों के स्वास्थ्य और मरीजों की सेवा के लिए नहीं हैं। खासकर अधिकतर निजी अस्पताल अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हैं। ज्यादातर निजी अस्पतालों में जितने डॉक्टर और नर्स हैं, उनसे भी ज्यादा वहां अस्पतालों का मुनाफा बढ़ाने वाले लोग होते हैं। सर्जनों को वहां मोटा वेतन अमूमन दिया ही इसलिए जाता है कि वे बड़ी संख्या में सर्जरी करेंगे और अस्पतालों की आमदनी बढ़ाएंगे। मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, इसलिए डॉक्टरों को सेवा का उद्देश्य भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे भागते देखना मुझे दुखद लगता है। मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले नए डॉक्टरों को अपने पेशे के प्रति ईमानदार बने रहने की शपथ लेनी पड़ती है। इसे हिपोक्रेटिज की शपथ कहते हैं। प्राचीन यूनान के चिकित्सक हिपोक्रेटिज के नाम पर इस शपथ की शुरुआत ईसा पूर्व पांचवीं सदी में हुई थी। **यह शपथ इस तरह है**-किसी मरीज का नुकसान नहीं करूंगा। रोगी की बेहतरी के लिए तमाम उपाय अपनाऊंगा। दूसरे चिकित्सकों को अपना परिवार समझूंगा और नि:स्वार्थ भाव से उनकी चिकित्सा और सेवा करूंगा। घुटने पर चोट लगने के कारण जिस दिन मैं नई दिल्ली स्थित एक बड़े और नामचीन निजी अस्पताल में गई थी, उस दिन चिकित्सक के साथ मैं एक मरीज भी थी। लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर ने सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए, केवल पैसे के लिए मेरा हिप जॉयंट काटकर अलग कर, उसकी जगह घटिया इम्प्लांट लगाकर मुझे बर्बाद कर दिया। डॉक्टर होते हुए भी उस दिन वह हिपोक्रेटिज की शपथ भूल गए थे। सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि रोज अपने पेशे में लगे डॉक्टर कितनी बार हिपोक्रेटिज की शपथ भूलते होंगे। मानो अपने मुनाफे के लिए गैरजरूरी सर्जरी कर देना ही कम बड़ा अपराध न हो, अपना झूठ छिपाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मुझे झूठी रिपोर्ट सौंपकर और भी बड़ा अपराध किया। चूंकि मैं डॉक्टर रह चुकी हूं, इसलिए उनका झूठ पकड़ पाने में सफल हुई। जबकि रोज असंख्य लोग चिकित्सा की दुनिया में व्याप्त इस फर्जीवाड़े का शिकार होते होंगे। उस व्यक्तिगत त्रासदी के आठ महीने से ज्यादा हो गए, आज भी मेरे लिए वह दु:स्वप्न सरीखा है। मैं पहले की तरह स्वस्थ और स्वाभाविक जीवन में नहीं लौट पाई। मैं वर्कआउट नहीं कर पाती। ऐसे में, कितने दिन स्वस्थ रह पाऊंगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में मुझमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जटिलताएं बढ़ जाएंगी। जिस भी दिन यह इम्प्लांट टूट जाएगा, उस दिन व्हील चेयर के अलावा मेरे पास चलने का कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में व्याप्त यह दुष्प्रवृत्ति हालांकि पहले भी मुझे चिंतित, विचलित करती थी। पर व्यक्तिगत अनुभव के बाद मेरी चिंता कहीं और बढ़ गई है, जिसमें मेरे अपने जीवन की चिंता भी शामिल है। कुछेक डॉक्टरों की कारस्तानियों को देखते हुए अब चिकित्सकों पर मेरा भरोसा पहले की तरह नहीं रहा।

अमेरिकी फिल्म 'द गुड अर्थ' चीन के किसानों और महिलाओं के संघर्षपूर्ण इतिहास को दर्ज करती भावपूर्ण कहानी

चीन में हुई किसान-मजदूरों की वामपंथी क्रांति से तो ज्यादातर लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन सदियों से महिलाओं और वंचितों पर होने वाले अत्याचारों और शोषण की कहानियां, अमूमन देश-दुनिया के आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इसके राजनीतिक कारण रहे हैं। यही वजह है कि चीन के दो लेखकों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने के बावजूद हम चीनी साहित्य-समाज के बारे में कम ही जानते हैं। यह विडम्बनापूर्ण है कि दुनिया भर में चीनी समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे लोकप्रिय लेखिका रही हैं अमेरिकी मूल की लेखिका पर्ल एस बॅक। पर्ल एस बॅक के बाद संभवत: वैसी लोकप्रियता मो यान को ही मिल पायी जिन्हें 2012 में साहित्य के नोबेल से नवाजा।

बहरहाल, पर्ल एस बॅक का शुरुआती जीवन चीन में ही बीता। वयस्क पर्ल भी चीन के अन्हुई प्रांत में कई वर्षों तक रहीं और उनके लेखन में यहीं के चीनी समुदाय का बहुत जीवंत वर्णन है। उन्होंने झेनजियांग प्रांत और उसके करीबी इलाकों के समाज, संस्कृति और इतिहास को भी सूक्ष्मता से देखा और अध्ययन किया. उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 'द गुड अर्थ', चीन के समाज की गहरी समझ और अभिव्यक्ति का सशक्त उदाहरण है। इसी उपन्यास पर आधारित थी 1937 में बनी फिल्म 'द गुड अर्थ'। फिल्म की कहानी है वांग लुन नाम के गरीब किसान की, जो एक अमीर किसान के खेतों में काम करता है। उसका विवाह होता है, उसी किसान के घर में काम करने वाली युवा लड़की ओ लान से। दोनों बहुत मेहनत से अपना घर बसाते हैं और कुछ जमीन भी खरीद लेते हैं। वांग लुन और ओ लान के तीन संतानें होती हैं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अकाल पड़ जाता है। हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद दो जून रोटी की भी किल्लत हो जाती है तो वांग लुन जमीन बेच देने का निश्चय करता है। ओ लान अड़ जाती है कि कुछ भी हो, ज़मीन नहीं बेचेंगे। तब वे फैसला करते हैं कि जब तक सूखे और अकाल जैसे हालात हैं वे गांव छोड़ कर कहीं और गुजारा कर लेंगे। अन्हुई प्रांत छोड़ कर वे दक्षिण चीन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी कोई खास काम ना मिलने के कारण इस परिवार को भीख मांग कर गुज़ारा करना पड़ता है। ओ लान सारे कष्टों का बहुत दृढ़ता से सामना करती है और वांग लुन की हिम्मत नहीं टूटने देती। सूखे और अकाल की स्थिति अब खत्म हो गई है। ये जान कर वांग लुन परिवार फिर वापिस आता है और अपनी ज़मीन पर खेती शुरू करता है। इसी बीच किसान-श्रमिकों की क्रांति होती है और वे अपने सामने उस अमीर घर को नष्ट होता देखते हैं जहां वे पहले काम करते थे। वांग लुन और ओ लान अपनी मेहनत से एक बार फिर खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन समृद्धि अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आती है। वांग लुन को एक युवा स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह ओ लान से दूसरा विवाह करने की इच्छा जाहिर करता है। ओ लान जीवन के संघर्षों से थक चुकी है, लेकिन वांग लुन की बात उसका दिल तोड़ देती है। फिर भी वह ओ लान के दूसरे विवाह के लिए राज़ी हो जाती है। इसी बीच उनके इलाके में टिड्डियों का हमला हो जाता है जिससे उनकी सारी फसल नष्ट होने के कगार पर आ जाती है और एक बार फिर वांग लुन परिवार जुट जाता है अपनी फसलों को बचाने में। थकी-हारी ओ लान आखिरकार दम तोड़ देती है। उसके जाने के बाद वांग लुन को एहसास होता है कि ओ लान उसके लिए उतनी ही जरूरी थी

लेखक-प्रगति सक्सेना

जितना कि एक किसान के लिए उसकी जमीन। एक किसान परिवार की संवेदनशील कहानी के जरिये लेखक पर्ल एस बॅक ने चीन के समाज, संस्कृति, परिवार, महिलाओं की स्थिति को सशक्त रूप से हाइलाइट किया। निर्देशक सिडनी फ्रेंकलिन ने इसे बखूबी पर्दे पर उतारा, लेकिन विडम्बना ये कि चीन के समाज पर बनी इस फिल्म की लगभग सभी मुख्य भूमिकाएं निभाई अमेरिकी कलाकारों ने। वांग लुन की भूमिका में थे पॉल मुनी और ओ लान का किरदार निभाया लूइज राइनर ने। कुछ एशिया मूल के कलाकारों ने अन्य भूमिकाएं निभाईं जो बहुत छोटी छोटी थीं। इससे हॉलीवुड में निहित रंगभेद और नस्लभेद को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ। बहरहाल, इस बात ने इंकार नहीं किया जा सकता कि पॉल मुनी और जर्मन मूल की लूइज राइनर ने अपने किरदारों पर बहुत मेहनत की और गजब का अभिनय किया। लूइज राइनर को 1935 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1938 में भी उन्हे 'द गुड अर्थ' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनके शुरुआती जर्मन लहजे को छोड़ दिया जाए तो 'द गुड अर्थ' में मितभाषी, दबी हुई, संवेदनशील लेकिन मेहनतकश महिला के तौर पर उन्होने उन्नीसवीं सदी की चीनी महिलाओं की स्थिति का दमदार चित्रांकन किया। लुइज राइनर ने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वे इस भूमिका के लिए राजी नहीं थीं, लेकिन चूंकि स्टुडियो के साथ उनका कांट्रैक्ट था इसलिए वे इस रोल से इंकार भी नहीं कर सकती थीं। उन्हें दक्षिण एशियाई दिखाने के लिए, सोचा गया कि उन्हे एक मास्क लगाया जाए. इससे उन्होंने साफ इंकार कर दिया। लंबे बहस-मुबाहिसे के बाद यह निश्चित हुआ कि मास्क नहीं बल्कि मेकअप के जरिए ही ऐसा किया जाएगा। एक चीनी स्त्री के तौर तरीके सीखना भी लुइज के लिए चुनौती थी।

पछियों का संसार: वायुमार्ग से आए शिशिर के प्रवासी

यह सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक, बार-हेडेड गूज (सफेद हंस) के झुंड में एक नन्हे परिंदे की कहानी है। कहानी गूज के मध्य एशिया से भारत तक की यात्रा से जुड़ी है। झुंड में से एक वायुराज नामक युवा हंस, थोड़ा उत्सुक और जिज्ञासु है। यह वायुराज की, तिब्बत पठार से निकल कर, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर उड़ान भरते हुए भारत पहुंचने की पहली यात्रा थी। वह नए दृश्यों और अन्य पक्षियों को देखने समझने के लिए अत्यंत उत्सुक था। उड़ान शुरू होने से पहले वायुराज की मां ने उसे हल्की चेतावनी भी दी कि उसे झुंड के साथ-साथ रहना होगा। झुंड 5500-6000 मीटर की ऊंचाई पर लम्बी यात्रा तय कर हिमालय को पार कर, गुजरात में कच्छ के छोटे रण पर ठहराव लेने को उतरा। झुंड का एक हिस्सा रास्ते में पहले ही भारत के पूर्वी भाग असम की और अग्रसर हो चुका था। वायुराज का झुंड जैसे ही कच्छ के छोटे रण पर उतरा, वायुराज फ्लेमिंगो और दसमोसाइल क्रेन से मंत्रमुग्ध हो झुंड से कुछ बिछड़ सा गया। वह फ्लेमिंगो और क्रेन को उत्साहित हो निहार ही रहा था कि रण के एक सुदूर कोने में वायुराज को बादामी रंग के स्तन वाले अद्भुत रेड-ब्रेस्टेड गूज दिखाई दिए। उसने पास खड़े फ्लेमिंगो जोड़े से पूछा तो पाया कि यह रेड-ब्रेस्टेड गूज सामान्य तौर पर अपनी सर्दियां बिताने भारत आते हैं और उन्हें यहां देख पाना एक दुर्लभ दृश्य ही था। वायुराज बादामी रंज वाले गुज को देख इतना मोहित हो गया था कि उसने अपने झुंड के हॉर्न की आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वह पीछे रह गया। गूज का झुंड दक्षिण भारत के पॉइंट कैलीमेर सैंक्चुअरी की और बढ़ गया था। नन्हे वायुराज को जब ज्ञात हुआ कि वह अपने झुंड से बिछड़ गया है, वह घबरा गया और बेचैन हो पास बैठे डेमोइसेल क्रेन से पूछा कि उसका झुंड संभवत: किस और गया होगा? डेमोइसेल क्रेन ने वायुराज को बताया कि हर वर्ष बार-हेडेड गूज भारत के कई हिस्सों में अपनी सर्दियां बिताते हैं, जैसे ही असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड लगभग सभी तटीय स्थानों पर उनके पाए जाने की संभावना हो सकती है। वायुराज चिंतित हुआ कि इतने बड़े देश में वह अपने झुंड से पुन: कैसे मिल पाएगा? नलसरोवर में वायुराज ने घास की नोक पर फारेस्ट वैगटेल बैठा मिला। पूछने पर वैगटेल ने वायुराज को बताया कि नलसरोवर में तो गूज का कोई झुंड नहीं उतरा, किन्तु संभवत: वे राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गए होंगे, क्योंकि राजस्थान गुजरात के समीप है और पहले नदजीकी स्थानों पर तलाशना आसान होगा, इसलिए वायुराज केवलादेव जाने का निश्चय करता है। केवलादेव पहुंचने पर वायुराज एक बार पुन: वहां कि सुंदरता और पक्षियों की विविधता को देख अत्यंत उत्साहित हो जाता है। एक बार को तो वह भूल भी गया की वह अपने झुंड से बिछड़ गया है।

शिकायतकर्ता पर भी गाजः अभिलेख पेश नहीं कर सका संचालक

योगराज व उनकी पत्नी शशिलता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई

बिना लाइसेंस बीज, उर्वरक और कीटनाशक बेचना पाया गया

बीज-उर्वरक के अवैध भंडारण और विक्रय पर दो एफआइआर

जांच के दौरान शशिलता पारधी द्वारा शासकीय कार्य में सहयोग न करने तथा अधिकारियों के साथ अभद्रता की गई

बालाघाट। जागत गांव हमार

जिले में नियम विरुद्ध बीज, उर्वरक व कीटनाशक बेचने के बढ़ते मामलों को रोकने कृषि विभाग की कार्रवाई जारी है। विभागीय अधिकारियों ने नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बम्हनी में सत्यनाम कृषि केंद्र के संचालक थमनदास पटले और इसी गांव के योगराज पारधी के घर औचक निरीक्षण किया, जहां बिना लाइसेंस बीज, उर्वरक और कीटनाशक बेचना पाया गया। कृषि उपसंचालक राजेश खोब्रागढ़े की अनुशंसा और कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर थमनदास पटले व योगराज पारधी के खिलाफ नवेगांव थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। खास बात है कि कृषि विभाग की टीम थमनदास पटले की शिकायत पर बम्हनी औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। इसमें थमदास ने पड़ोस के योगराज पर कपड़े की दुकान की आड़ में बीज का विक्रय करने की शिकायत की थी।

जब अधिकारियों की जांच आगे बढ़ी तो शिकायतकर्ता थमनदास भी इसकी चपेट में आ गया। जांच में अधिकारियों को थमनदास की दुकान के पीछे गोदाम में बीज, उर्वरक व कीटनाशक का भंडारण मिला। इतना ही नहीं, क्रय-विक्रय और भंडारण से संबंधित दस्तावेज मांगने पर थमनदास वैधानिक स्त्रोत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। कृषि उपसंचालक राजेश खोब्रागढ़े ने बताया कि वह स्वयं और बीज निरीक्षक सुनील कुमार बागड़े ने बम्हनी में निरीक्षण किया। यहां सत्यनाम कृषि केंद्र के संचालक थमनदास पटले बीज विक्रय से संबंधित अनुज्ञप्ति तो प्रस्तुत किया गया, लेकिन वैधानिक स्त्रोत प्रमाण पत्र के अलावा उर्वरक व कीटनाशक दवाओं के क्रय-विक्रय एवं भंडारण से संबंधित किसी भी प्रकार अभिलेख पेश नहीं किया गया।

विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया

संदिग्ध मानते हुए एनएफएल कंपनी का यूरिया 36 बैग, इफको कंपनी का डीएपी 10 बैग, एपीएस 13 बैग, राजनांदगांव छग की कंपनी का बायो सुपर दानेदार व पाउडर 94 बैग तथा 20:10:20 के तीन बैग कुल 156 बैग का अवैध रूप से भंडारण करना पाया गया। पुलिस ने थमनदास पटले के खिलाफ धारा 420, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3, धारा-7 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

शासकीय कार्य में पहुंचाई बाधा

खोब्रागढ़े ने बताया कि थमनदास पटले के पड़ोस में रहने वाले योगराज पारधी के घर में एक कपड़े की दुकान है। इसी दुकान में पारधी द्वारा हैदराबाद की एक कंपनी का सत्यरूप धान बीज करीब 30 किलो विक्रय के लिए रखा हुआ पाया गया। योगराज पारधी की पत्नी शशिलता पारधी ने अधिकारियों को बताया कि पति योगराज हैदराबाद की इसी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बीज भूमि एग्रो-केम कोसमी बालाघाट से लाया है।

हैदराबाद की कंपनी को आर्थिक लाभ

जांच में पाया गया कि पारधी द्वारा हैदराबाद की उक्त कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाने की मंशा से बगैर अनुज्ञप्ति के बीच के क्रय-विक्रय व भंडारण कर व्यापार किया जा रहा है। जांच के दौरान शशिलता पारधी द्वारा शासकीय कार्य में सहयोग न करने तथा अधिकारियों के साथ अभद्रता की गई। इसी आधार पर योगराज व उनकी पत्नी शशिलता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कृषि केंद्र संचालक थमनदास ने योगराज के खिलाफ शिकायत की थी। निरीक्षण के दौरान दोनों के घर व दुकान में बीज-उर्वरक का अवैध भंडारण, कपड़े की दुकान की आड़ में बिना लाइसेंस इनका विक्रय करना तथा वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर दोनों के खिलाफ कलेक्टर साहब के आदेश पर नवेगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

राजेश खोब्रागढ़े, उप संचालक, कृषि विभाग बालाघाट

कृषि विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण में बम्हनी में बीज-उर्वरक विक्रय में गड़बड़ी मिली है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर दोनों प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा मामले को जांच में लिया गया है।

कमल सिंह गेहलोत, नवेगांव थाना प्रभारी

खाद्य तेलों का दाम सीमित रहने की उम्मीद

गेहूं की बोवनी 92 प्रतिशत, सरसों ने तोड़ा रिकॉर्ड

इंदौर। जागत गांव हमार

रबी सीजन में गेहूं की बोआई का क्षेत्रफल बीते वर्ष से पीछे बना हुआ है। 15 दिसंबर तक जारी आंकड़ों के अनुसार देश में गेहूं की बोआई बीते वर्ष के मुकाबले 92 प्रतिशत क्षेत्रफल में है। किसानों और कृषि विज्ञानियों की नजरें मौसम पर टिकी हुई है। ठंड का जोर बढ़ने पर अच्छे उत्पादन की उम्मीद की जा सकेगी। गेहूं के साथ चने और दलहन में बोआई के आंकड़े कमजोर है। बाजार का आंकलन है कि दालों की महंगाई अगले साल भी बनी रहेगी। हालांकि रबी क्षेत्रफल को देखकर खाद्य तेलों के दामों में राहत अगले साल भी जारी रहने की उम्मीद है। गेहूं का कुल क्षेत्रफल सामान्य तौर पर 307.32 लाख हेक्टेयर माना जाता है। ताजा स्थिति में इसमें आठ प्रतिशत की कमी दिखाई दे रही है। हालांकि बीते वर्ष के मुकाबले बोआई क्षेत्रफल का फासला कही अधिक दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बीते वर्ष343.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोआई हुई थी। देश के लगभग सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में इस साल गेहूं की बोआई कम है। दरअसल दो साल पहले गेहूं की विश्व में कमी हुई थी।

जमकर निर्यात हुआ

रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यह स्थिति बनी थी। उस दौरान भारत से गेहूं का निर्यात खोला गया था। जमकर निर्यात हुआ और स्थानीय बाजारों में गेहूं के दाम 3500 रुपए क्विंटल के पार पहुंच गए थे। नतीजा बीते वर्ष गेहूं की उपज लेने में किसानों की रुचि बढ़ी और गेहूं की बोआई ज्यादा हुई। नतीजा क्षेत्रफल रिकार्ड 343 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया।

दालें भी घटी, सरसों बढ़ी

न सिर्फ गेहूं बल्कि रबी सीजन में दलहन का बोआई क्षेत्र भी घटता दिख रहा है। बीते सीजन के 139.98 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल दलहन की बोआई 128.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। रबी में खासतौर पर बोई जाने वाले दोनों दलहन चना और मसूर दोनों के ही रकबे में कमी देखी जा रही है। चने में तो 10 प्रतिशत तक की कमी आई है। हालांकि रबी में दलहन के मुकाबले सरसों की बोआई बढ़ी है।

सस्ती उपलब्धता के आसार

सरसों का बोआई क्षेत्रफल 73.06 सामान्य माना जाता है। इस रबी सीजन में यह बढ़कर 92.46 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। बीते साल रिकार्ड 90.17 लाख हेक्टेयर में सरसों बोई गई थी। इस साल उससे भी तीन प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे में सरसों के रिकॉर्ड उत्पादन से अगले साल तेलों की अच्छी और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित होने के आसार हैं।

बीते वर्ष से कम रहेगा गेहूं का रकबा

अब माना जा रहा है कि गेहूं का क्षेत्रफल तो बीते वर्ष से कम ही रहेगा लेकिन अंतिम तौर पर सामान्य बोवनी क्षेत्रफल को हासिल कर लिया जाएगा। जल्दी बोवनी वाले क्षेत्रों में मौसम की गर्मी भी परेशा कर रही है। दरअसल दाने आने के समय मौसम गर्म रहने से दाने कम होने से उत्पादकता पर असर पड़ सकता है। मप्र-उप्र जैसे राज्यों में अब सर्दी ने जोर पकड़ा है ऐसे में देरी से बोवनी वाले क्षेत्रों में उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है।

-खाद्य, सहकारी व वेयरहाउस के जीएम को थमाया नोटिस

धान की खरीदी में लापरवाही पर कटनी कलेक्टर ने दिखाई सख्ती

कटनी। जागत गांव हमार

कटनी में पिछले 21 दिन से शासन स्तर पर किसानों से उनकी उपज (धान) को खरीदी केन्द्रों के माध्यम से खरीदने का कार्य चल रहा है। इस पूरे कार्य में किसानों को कोई दिक्कत का समाना न करना पड़े, इसके लिए नान (मप्र नागरिक आपूर्ति निगम), खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग सहित मप्र वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जैसे चार विभागों को शामिल किया जाता है। ताकि किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, बरदाना अच्छे स्तर का हो, जिससे उनकी धान जल्द तुलकर उनके खाते में पैसे चले जाएं। लेकिन उपार्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अधिकारियों की सुस्त रवैया को देखते हुए कटनी कलेक्टर अवि प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से चारों विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें उपार्जन से जुड़ी समीक्षा में फटे बरदाना, छन्ना लगाने, परिवहन कार्य में सुस्ती पर गहन नाराजगी जाहिर करते हुए नान अधिकारी अमित गौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

महज 47 प्रतिशत ही परिवहन

कटनी के 79 धान खरीदी केंद्रों में अब तक 82 हजार 625 मीट्रिक टन धान उपार्जित की गई है, जिसमें से महज 47 प्रतिशत ही परिवहन हुआ है। जो करीब 39 हजार 241 मीट्रिक टन होता है। वहीं, स्वीकृत पत्रक में 13 फीसदी हुआ, जिसके चलते कृषकों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कलेक्टर ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी बालेंद्र शुक्ला, मध्यप्रदेश वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के जीएम योगेंद्र सिंह सेंगर सहित सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील को भी नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।

व्यवस्थाओं को बढ़ाएं

वहीं, सभी को हिदायत देते हुए कहा कि खराब मौसम और बारिश की संभावना के मद्देनजर उपार्जन केन्द्रों में त्रिपाल और अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ाएं। इसके साथ परिवहन में गति को और बढ़ाएं, ताकि किसानों को उनकी उपज की मूल्य जल्द से जल्द उनके खाते में पहुंच सके।

बिजली पैदा करने के लिए खड़ी की विशाल टरबाइन

खरगोन में किसान ने कुंदा नदी पर बना दिया डैम

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बिजली कटौती और पानी की समस्या से निजात पाने के लिए एक किसान ने अद्भुत जज्बा और जुनून दिखाया है, किसान ने कुंदा नदी पर एक विशाल बांध बनाया है। किसान ने बिजली पैदा करने के लिए विशाल टरबाइन खड़ी कर दी है। इसके लिए किसान ने 12 साल पहले अभियान शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कि ओर से अब तक इसके लिए कोई मदद नहीं मिली है। किसान ने बताया कि आर्थिक मदद नहीं मिलने से एक मेगावॉट बिजली पैदा करने का किसान का सपना अधूरा रह गया है। वहीं किसान ने इस पॉवर प्लांट को खड़ा करने में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। किसान ने कहा कि उन्हें आस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मदद करेंगे।

करोड़ों लगा चुका किसान- खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर भगवानपुरा विकासखंड के छोटे से गांव बाड़ी के 58 वर्षीय किसान मोहनलाल जांगड़े ने वर्ष 2011 में बिजली और पानी की समस्या से निजात पाने के लिए एक पहाड़ जैसा निर्णय लिया। उन्होंने करीब 600 फीट लंबाई वाली विशाल कुंदा नदी पर पॉवर प्लांट खड़ा करने का निर्णय लिया और नदी पर बांध बनाने की शुरुआत कर दी। हायर सेकंडरी और मैकेनिक से आईटीआई डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त करने वाले मोहनलाल जुझारू किसान हैं। करोड़ों रुपये लगाने के बावजूद आज भी प्रोजेक्ट पूरा करने का उनका जज्बा जुनून बरकरार है।

बिजली की कमी के कारण लिया निर्णय

किसान मोहनलाल जांगड़ा ने बताया वर्ष 2009 में पिता का निधन हुआ और उनके दश कर्म करने के लिए कुंदा नदी के किनारे गया था। इस दौरान गर्मी के मौसम में नदी में पर्याप्त पानी नहीं था और किसान सिंचाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब मुश्किल से 6 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। पर्याप्त बिजली नहीं मिलने और पानी की समस्या बनी रही। पानी और बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए मेरे मन में कुंदा नदी पर डेम और बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन बनाने का विचार आया और इस तरह 2011 में मैंने पावर प्लांट बनाने का अभियान शुरू कर दिया।

किसान ने बनाया 600 फीट लंबा डेम

किसान ने अथक प्रयास कर तीन ग्राम पंचायत की सीमा पर बांध का निर्माण किया। यहां कुंदा नदी पर 600 फीट से अधिक लंबा और करीब 5 फीट चौड़ा बांध तैयार किया है। करीब 15 फीट ऊंचा सीमेंट का आर्च बांध बनाया गया है। इसकी गहराई करीब 15 फीट बताई जा रही है। प्रोजेक्ट की डीपीआर मंजूरी और लेटर के साथ ही कलेक्टर द्वारा डेम साइट पर 3100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर के साथ पॉवर पर्चेस एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन किसान को अब तक सब्सिडी की राशि नहीं मिली है। दरअसल केंद्र की योजना में 90 फीसदी सब्सिडी निर्धारित था।

पीथमपुर की फैक्ट्री से मिला अनुभव

किसान मोहनलाल जांगड़े ने मैकेनिकल में डिप्लोमा करने के बाद लंबे समय तक पीथमपुर फैक्ट्री में काम किया। इसके चलते उन्हें मैकेनिक के साथ सिविल और इलेक्ट्रिकल कामकाज का अनुभव मिला। साथ ही पीथमपुर में ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू किया। इसके चलते इतनी राशि वे प्रोजेक्ट पर लगा सके प्रोजेक्ट का काम धीरे-धीरे होता चला गया। डेम बनाने के बाद किसान ने अपने खेत तक पानी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की लंबी पाइप लाइन भी डाली है।

14 मीटर 200 डाया का टरबाइन

मोहनलाल का कहना है 14 मीटर 200 दया का टरबाइन है। एक बार प्लेनेटरी गियरबॉक्स चलाने पर टरबाइन 252 बार घूमता है। एक बार में करीब 100 किलोवाट टी बिजली तैयार की जा सकती है और केंद्र शासन मदद करता है तो इसी टरबाइन से एक मेगावाट बिजली जनरेट हो सकती है।

इंदौर के जीएसआईटीएस से ली थी राय

किसान मोहनलाल ने बताया इंदौर के जीएसआईटीएस पावर प्लांट के लिए जानकारी ली। वहां से पता चला कि केंद्र शासन की योजना में सब्सिडी मिलता है। योजना की पूरी जानकारी के लिए अक्षय ऊर्जा विभाग जो अब न्यू एंड रिनिवल एनर्जी विभाग के नाम से जाना जाता है, वहां से मिली गाइडलाइन के हिसाब से ग्राम पंचायत, जल संसाधन विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, वन विभाग, हाइड्रो मेट्रोलॉजी आदि विभागों से एनओसी और परमिशन लेने में ही 2 साल लग गए।

लगातार 11वें हफ्ते दर्ज की गई गिरावट

सावधान! देश के बांधों में पानी का स्तर गिरा

इधर, देश के बांधों में पानी का स्तर निचले स्तर पर चला गया है। देश के 150 बड़े बांधों में पानी का स्तर 10 साल के निचले स्तर पर है। इन बांधों में 30 जलाशय ऐसे हैं जिनमें 40 परसेंट से कम पानी है। सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है। सीडब्ल्यूसी ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में बताया है कि बांधों में पहले पानी और भी कम था, लेकिन हाल में आए मिचौंग तूफान की बारिश से इस कमी को पाटने में थोड़ी मदद मिली। मिचौंग से हुई बारिश से बांधों में थोड़ा जलस्तर बढ़ा, लेकिन यह सामान्य से अब भी कम बना हुआ है। बड़ी बात ये है कि लगातार 11वें हफ्ते भी बांध में पानी का स्तर सामान्य से कम है। 21 दिसंबर को 150 बांधों में 110.943 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। पानी का यह स्तर कुल क्षमता 178.784 बीसीएम का 62 परसेंट है।

कितना है पानी का स्तर-पिछले साल की क्षमता से देखें तो अभी बांधों में 18 परसेंट कम पानी है जबकि पिछले 10 साल में 32 परसेंट कम पानी है। देश के 10 राज्यों में बांधों में पानी का स्तर सामान्य से कम है जबकि आंध्र प्रदेश में हालात सबसे अधिक खराब है। दक्षिण भारत के राज्यों में बांधों में सामान्य से 41 परसेंट कम पानी है। हालांकि पिछले हफ्ते से स्थिति ठीक है, क्योंकि तब पानी का स्तर सामान्य से 50 परसेंट था।

किसानों की चिंताएं बढ़ीं

बांधों में कम पानी से किसान और कृषि क्षेत्र की चिंताएं बढ़ गई हैं। अभी रबी सीजन चल रहा है जिसमें कई फसलें खेतों में खड़ी हैं। इन फसलों में सिंचाई के लिए पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बांधों के जरिये ही कई राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। किसानों के लिए एक अच्छी बात ये है कि दिसंबर में बारिश ठीक हुई है जिससे रबी फसलों को जान मिली है। कुछ दिनों के लिए सिंचाई की समस्या से छुटकारा मिला है।

इन क्षेत्रों में हालत खराब

उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र के बांधों की स्थिति बाकी हिस्से के बांधों से ज्यादा खराब है। दक्षिण हिस्से के जलाशयों में पहले वाली स्थिति ही है। यानी यहां पानी का स्तर उस का तस है। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तरी क्षेत्र के 10 बांध ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर 63 परसेंट तक बना हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र के बांधों में पानी का स्तर सामान्य स्तर का 74 परसेंट है। दक्षिणी क्षेत्र में पानी का स्तर 42 परसेंट तक है।

2022-23 में उत्पादन दर 2 फीसदी गिरी, 10 माह में 1.80 लाख पशुओं की मौत

लंपी रोग से देश के मिल्क प्रोडक्शन पर बुरा असर

भोपाल। जागत गांव हमार

मवेशियों के लिए मुसीबत का कारण बना लंपी स्किन रोग देश के दूध उत्पादन को प्रभावित किया है। लंपी रोग के प्रकोप के चलते दुधारू पशुओं के दूध की मात्रा घट गई, जिसके चलते 2022-23 में देश में दूध उत्पादन दर धीमी होकर 2 फीसदी तक गिर गई है। वहीं, थ्रिप्स रोग की वजह से मिर्च की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते देश का कुल मिर्च उत्पादन भी घट गया है। सरकार ने बीते दिन लोकसभा में आंकड़े बताए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में लंपी रोग के प्रकोप से बड़े पैमाने पर मवेशी चपेट में आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मई 2022 से मार्च 2023 तक लंपी रोग की वजह से 1.86 लाख से ज्यादा पशुओं की मौत हुई और 32.80 लाख से अधिक पशु रोग से ग्रस्त हुए। लंपी रोग त्वचा रोग है और इससे पीड़ित पशु के शरीर में गांठ बन जाती है, जिससे पशु को बुखार आने लगता है। यह रोग इतना खतरना है कि पशु की मौत भी हो सकती है। लंपी रोग की चपेट में आने से दुधारु पशुओं की दूध मात्रा पर बुरा असर पड़ा, जिसके चलते देश का कुल दूध उत्पादन भी घट गया है।

दूध उत्पादन दर 2 फीसदी नीचे - केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि देश में दूध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2021-22 में 5.77 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.83 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि 2022-23 में दूध उत्पादन की धीमी वृद्धि के पीछे लंपी रोग मुख्य कारण था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक की स्थिति बरकरार रखता है।

थ्रिप्स रोग ने मिर्च का उत्पादन घटाया

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 2021-22 फसल सीजन में मिर्च की फसल थ्रिप्स रोग से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे फसल को काफी नुकसान हुआ, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर मिर्च का उत्पादन 2020-21 में 20.49 लाख टन से घटकर 2021-22 में 18.36 लाख टन रह गया। उन्होंने कहा कि फसल पर रोग का असर सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में था। इसके चलते पिछले वर्ष के उत्पादन 7.97 लाख टन से घटकर 2021-22 में 4.18 लाख टन हो गया। आंध्र प्रदेश में मिर्च उत्पादन 2021-22 में 4-5 टन प्रति हेक्टेयर की औसत वार्षिक उत्पादन से घटकर 1.86 टन प्रति हेक्टेयर हो गई।

धान के कम भाव होने पर किसान नाराज

रोज हंगामा, बार-बार बंद हो रही खरीदारी परेशानी में अन्नदाता

-बार-बार खरीदी बंद होने से किसान भी हो रहे परेशान, फिर मंडी प्रशासन नहीं ढूंढ पा रहा समस्या का स्थाई समाधान

श्योपुर। जागत गांव हमार

धान की बंपर आवक से श्योपुर की कृषि उपज मंडी में खासी रौनक विखर रही है। लेकिन धान के भाव को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति भी बन रही है। मंडी में विवाद की यह स्थिति व्यापारियों के द्वारा धान का भाव कम लगाने पर बन रही है। जिसकारण मंडी में खरीदी कार्य बार-बार बंद हो रहा है। बार-बार खरीदी बंद होने के कारण जहां मंडी का क्रय विक्रय कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं अन्नदाता कहे जाने वाले किसान भी परेशान हो रहे है। लेकिन इसके बाद भी मंडी प्रशासन इस विवाद का स्थाई समाधान नहीं ढूंढ पाया है। जिसके चलते श्योपुर मंडी की विवाद होने को लेकर भी एक खराब पहचान बनती जा रही है। ऐसे में जरूरत है मंडी प्रशासन को इस विवाद का स्थाई समाधान ढूंढने की। यहां बता दें कि पहले श्योपुर मंडी में धान की खरीदी नहीं होती थी, जिस कारण श्योपुर क्षेत्र के किसान अपने धान की फसल को बेचने के लिए राजस्थान की मंडियों की तरफ रुख करते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से श्योपुर की कृषि उपज मंडी में धान की खरीदी शुरू हो गई है। चूंकि श्योपुर क्षेत्र में बडी संख्या में किसान धान की फसल करते है, जो अब धान की फसल बेचने के लिए श्योपुर मंडी में पहुंच रहे है। जिस कारण मंडी में किसानों की रेलमपेल बनी हुई है। धान लेकर किसान इतनी संख्या में पहुंच रहे है कि उनकी धान की फसल एक दिन में भी बिक नहीं पा रही है। इससे किसानों को मंडी में रात गुजारनी पड रही है। किसानों की इस परेशानी को मंडी में भाव कम लगाने को लेकर आए दिन बनने वाली विवाद की स्थिति भी बढ़ा रही है। मंडी में ऐसा कोई दिन नहीं जाता,जिस दिन मंडी में धान का भाव कम लगाने की बात को लेकर हंगामा न होता हो। कई बार यह हंगामा विवाद में बदल जाता है और खरीदी बंद हो जाती है।

सबसे ज्यादा परेशानी किराए के ट्रैक्टर-ट्रॉली से उपज बेचने वाले किसानों को

कृषि उपज मंडी में भाव कम लगाने की बात को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनने से मंडी प्रशासन को खासी असुविधा हो रही है। वहीं किसान भी परेशान हो रहे है। सबसे ज्यादा उन छोटे किसानों को उठानी पड़ रही है, जो किराए के ट्रैक्टर-ट्रॉली से धान की फसल लेकर बेचने के लिए आते हैं। क्योंकि विवाद की स्थिति बनने से खरीदी बंद हो जाती है। जिससे किसानों की धान की एक दिन में बिकने वाली फसल दो से तीन दिन में बिक पा रही है और फसल बिकने तक किसानों को मंडी में रुकना पड़ता है। जिस कारण किसानों की समय और भाड़े के रूप में धन की दोहरी हानि हो रही है।

भाव कम लगाने पर किसान हंगामा कर देते है और व्यापारियों से भी उलझ जाते हैं। जिस कारण व्यापारी खरीदी बंद कर देते हैं। हम किसान और व्यापारियों को समझाइस देकर खरीदी शुरू करवाते हैं। हम ऐसे प्रयास भी करेंगे कि भाव को लेकर बनने वाली विवाद की स्थिति का स्थाई रूप से समाधान हो जाए।

एसडी गुप्ता सचिव, कृषि उपज मंडी श्योपुर

मध्य प्रदेश की सड़कों पर लगभग आठ लाख गौवंश बेसहारा

सड़कों पर अब नहीं दिखेंगी लावारिस गाय, राज्य सरकार बनएगी बाड़े

भोपाल। जागत गांव हमार

- एनएच अथारिटी निर्माण में सहयोग करतार फेंसिंग कराएगी
- भोपाल-जबलपुर के बीच बनाया जाएगा प्रदेश का पहला गोठान
- राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर 300 किमीके दायरे में बनाए जाएंगे तीन
- एक एकड़ में बनेगा एक गोठान, करीब 100 गायों की रहेगी क्षमता

प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर छुट्टा घूमते गोवंशों को सुरक्षित रखने के लिए गोठानों का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश में सबसे पहले भोपाल-जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर तीन गोठान बनाए जाएंगे। दोनों शहरों के बीच 300 किलोमीटर के दायरे में तीन गोठानों को विकसित किया जाएगा, जिनमें लगभग 100 गौवंश रखे जा सकेंगे। इनका निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश गोसंवर्द्धन बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इनके निर्माण से लेकर गोवंश के रखरखाव में राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पशुपालन विभाग का पूरा सहयोग रहेगा। गौरतलब है कि प्रदेश की सड़कों पर लगभग आठ लाख गौवंश बेसहारा हैं। सर्दियों की शुरुआत से गर्मियों तक राजमार्गों पर इनकी संख्या बढ़ जाती है।

हेलीपैडनुमा होंगे गोठान, लागत एक लाख- गोठान का अर्थ गायों के बैठने की खुली व्यवस्था है। इनका निर्माण करने के लिए लगभग एक एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगभग 50 हजार से एक लाख तक की लागत आएगी। ये गोठान हेलीपैडनुमा गोलाकार होंगे। इनमें फर्श भी बनाए जाएंगे। इसके आसपास पानी की व्यवस्था की जाएगी और गौमूत्र का संग्रह करने के लिए भी स्थान बनाया जाएगा।

हाईवे अथारिटी कराएगी फेंसिंग- राजमार्ग से लगे जंगल की तरफ इन गोठानों का निर्माण होगा। नेशनल हाईवे अथारिटी द्वारा गोठान के निर्माण में सहयोग करते हुए तार फेंसिंग कराई जाएगी, जिससे गौवंश इससे निकलकर सड़क पर नहीं जा सकें। इसके अलावा आथरिटी के कर्मचारी मार्ग से गौवंश को पकड़कर गोठान तक पहुंचाएंगे। इन गोठानों में करीब 100 गौवंश आसानी से ठहर सकेंगे। वर्ष 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दतिया आए थे। जब वह सड़क मार्ग से एक कार्यक्रम के लिए रवाना हुए तो गोवंश का झुंड देखने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इनका व्यवस्थापन करने के लिए कहा था। इसके बाद से ही गोठानों का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है।

भोपाल-जबलपुर के बीच ब्लैक स्पॉट

भोपाल से जबलपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर बाडी-बरेली, चिकलौद, ओबेदुल्लागंज क्षेत्र ब्लैक स्पाट बन गया है। यहां पर सबसे ज्यादा बेसहारा गौवंश हाईवे पर बैठे रहते हैं। आए दिन एक से दो पशुओं की मौत यहां से गुजरने वाले भारी वाहनों से टकराने से होती है। साथ ही कई बार यात्री वाहन भी हादसे के शिकार हो जाते हैं।

भोपाल से जबलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर 300 किलोमीटर के दायरे में तीन गोठान बनाने का प्रस्ताव है। इनका निर्माण होने से मार्ग पर विचरण करने वाले गौवंश की संख्या में कमी आएगी और उन्हें सुरक्षित स्थान मिल सकेगा। इस संबंध में जल्द ही जिलों के कलेक्टर से चर्चा की जाएगी।

अखिलेश्वरानंद गिरि, अध्यक्ष, गोसंवर्द्धन बोर्ड कार्य परिषद

ट्रेडर्स को रिटेल प्राइस घटाने के निर्देश

-खरीद टारगेट घटने पर सरकार का फैसला

चावल की महंगी कीमत से लोगों को राहत मिलेगी

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार की ओर से अक्टूबर सीजन में जारी चावल की खरीद बीते साल की समान अवधि की तुलना में करीब 13 फीसदी कम हुई है। पंजाब और हरियाणा में चावल खरीद टारगेट पूरा हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में सबसे कम खरीद हुई है। ऐसे में पहले से बढ़ी चावल की कीमतों में और उछाल की आशंका को देखते हुए सरकार ने चावल एसोसिएशन और ट्रेडर्स से खुदरा कीमतें घटाने के निर्देश दिए हैं। ताकि, पहले से महंगाई से परेशान आम जनता को चावल के और महंगे होने का सामना न करना पड़े। एक अक्टूबर को सीजन शुरू होने के बाद से ढाई महीने में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से भारत की चावल की खरीद एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 279.38 लाख टन से 12.7 प्रतिशत घटकर 243.85 लाख टन हुई है। हालांकि, सरकार को अगले कुछ महीनों में चावल खरीद बढ़ाने और इस कमी को पूरा करने का भरोसा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब और हरियाणा में खरीद पूरी हो चुकी है और टारगेट के बराबर खरीद हुई है। एफसीआई पंजाब में 124.08 लाख टन चावल खरीदने में सक्षम रहा है, जो पिछले साल से 2 प्रतिशत अधिक है। हरियाणा में 39.42 लाख टन खरीद हुई है, जो 2022 में 39.5 लाख टन खरीद से थोड़ा कम है। सबसे कम खरीद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में हुई है।

सरकार ने कहा-एसोसिएशन खुदरा कीमत घटाएं

केंद्र ने चावल एसोसिएशनों से तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत कम करने को कहा है। आधिकारिक नोटिफिकेशन में सरकार ने भारत में चावल उद्योग संघों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने सोमवार को प्रमुख चावल प्रॉसेसिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं तक जल्द पहुंचाने पर चर्चा हुई। प्रमुख चावल उद्योग संघों को सलाह दी गई कि वे अपने सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो।

चावल के एमआरपी और रिटेल प्राइस में भारी अंतर

बैठक में सुझाव दिया गया है कि जहां एमआरपी और वास्तविक खुदरा मूल्य के बीच बड़ा अंतर है, वहां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसे सही स्तर पर लाने की जरूरत है। यह आदेश थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राप्त मार्जिन में तेज वृद्धि की रिपोर्ट के बीच आया है। ऐसी रिपोर्ट आई हैं कि थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मिलने वाले मार्जिन में तेज वृद्धि हुई है, जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है।

ट्रेडर्स को सस्ता चावल उपलब्ध करा रहा एफसीआई

भारतीय खाद्य निगम ने राइस प्रॉसेसिंग इंडस्ट्री को बताया है कि अच्छी क्वालिटी वाले चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसे ओपेन मार्केट सेल स्कीम के तहत 29 रुपए प्रति किलोग्राम के रिजर्व मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है. यह भी सुझाव दिया गया कि व्यापारी ओपेन मार्केट सेल स्कीम के तहत एफसीआई से चावल उठाने पर विचार कर सकते हैं, जिसे उपभोक्ताओं को उचित मार्जिन के साथ बेचा जा सकता है।

-किसानों का वित्तीय संकट दूर करेगी सरकार

तीन लाख तक के कृषि लोन पर सभी तरह के सर्विस चार्ज

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों का वित्तीय संकट दूर करने के प्रयासों के तहत सरकार कृषि लोन तक पहुंच आसान बना रही है। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर सभी तरह के सर्विस चार्ज माफ होंगे। यह सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य तरह के फसल लोन पर लागू होगी। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि सरकार किसानों तक ऋण की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने बीते दिन लोकसभा में प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि सरकार किसानों को कृषि गतिविधियों में वित्तीय मदद देने के लिए कई बदलाव कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग ने सभी बैंकों को छोटे एवं सीमांत किसानों की कठिनाई और वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए तीन लाख रुपए तक के केसीसी लोन या फसल लोन के निपटारे, डॉक्यूमेंटेशन, सर्वे, खाता बही शुल्क समेत अन्य सभी तरह के सर्विस चार्ज माफ करने को कहा है।

गारंटी मुक्त कृषि लोन की सीमा बढ़ाई गई

केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गारंटी मुक्त कृषि लोन की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सलाह दी है कि वे अपनी लोन एसेसमेंट प्रॉसेस, लोन पॉलिसी में एक या अधिक क्रेडिट सूचना कंपनियों से क्रेडिट सूचना रिपोर्ट हासिल करने के लिए सही प्रावधानों का समावेश करें ताकि व्यवस्था में उपलब्ध जानकारी के आधार पर लोन संबंधी सही निर्णय हो सकें।

भूमि क्षेत्र और बोई गई फसल पर लोन सुविधा

केसीसी योजना विभिन्न श्रेणी के किसानों के लिए लोन तक आसान पहुंच पक्का करती है, जिसमें किसान, काश्तकार, बटाईदार आदि शामिल हैं। केसीसी योजना के तहत रूपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। केसीसी अपने आप में ओवरड्राफ्ट सुविधा है, जिससे स्वीकृत सीमा तक रूपे डेबिट कार्ड के जरिए रकम निकाली जा सकती है। अब फसल लोन का एसेसमेंट भूमि क्षेत्र और उगाई गई फसलों के आधार किया जाता है। खराब मौसम आदि के कारण मौजूदा केसीसी लोन के नए सिरे से व्यवस्थित करने के बाद राज्य सरकार या बैंकों के निर्णय के तहत किसानों को बैंक के पात्रता मानक के अनुसार जरूरत के हिसाब से लोन लेने की अनुमति है।

देश में गेहूं-धान के चक्कर में दलहन फसलों की उपेक्षा

भोपाल। जागत गांव हमार

इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है, लेकिन, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम बड़े दाल आयातक भी है। सवाल यह है कि ऐसा विरोधाभास क्यों? जवाब यह है कि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए दलहन फसलों की जितनी खेती होनी चाहिए थी, उस गति से रफ्तार नहीं बढ़ी। आजादी के बाद से ही हमारी पॉलिसी ऐसी रही है जिसमें गेहूं-धान की फसलों पर ज्यादा जोर दिया गया और दलहन फसलें पीछे छूट गईं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पुराने पन्नों को पलटने पर इसे लेकर दिलचस्प जानकारी सामने आती है। जिसमें साफ पता चलता है कि क्यों हम दालें इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। दरअसल, दालों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर हमने बहुत देर से चलना शुरू किया। अब हम जितना एरिया और उत्पादन बढ़ाते हैं उससे ज्यादा तेजी से खपत बढ़ जाती है। अरहर (तूर) दाल भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दालों में से एक है। इसका दाम 170 से 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले एक साल में ही अरहर दाल का दाम प्रति किलो 39 रुपए बढ़ गया है। दूसरी दालों का भाव भी लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। जब दलहन फसलों का रकबा देखेंगे तो वह बढ़ा जरूर नजर आएगा। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से इसकी खेती तितनी बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ी। जब हम प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता देखेंगे तो यह यह बात समझ में आ जाएगी। इस वक्त सालाना प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता पहले से घट गई है। 1951 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दालों की उपलब्धता 22.1 किलो थी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)